सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर आफ इंडिया का मुख पत्र–(पाक्षिक)

मुख्य सम्पादक : प्रीतीश चन्दा

वर्ष 2 अंक 2 7 जुलाई 1986 मूल्य 25 पैसे

पाकिस्तान में उफान

जनवादी अधिकारों की बहाली के लिए जनता एकजुट

जनरल जिया और उसके गुट के बर्बर एवं भ्रष्ट सैनिक शासन के विरुद्ध संघर्षरत पाकिस्तानी जनता को बेनजीर भुट्टो में आशा की किरण दिखाई दे रही है। बेनजीर भुट्टो को अपने स्व-निष्कासन के बाद पाकिस्तान लौटने पर पाकिस्तानी जनता से जो अभूतपूर्व प्रशंसा मिली और जिस प्रकार उनके स्वागत में पलक पांवड़े बिछाए गए, उससे तो यही जाहिर होता है। रावलपिंडी से मुलतान तक, [illegible] से लाहौर तक तथा, उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रदेश में बेनजीर भुट्टो की असंख्य जन-सभाओं में जिस प्रकार लाखों की संख्या में भाग लिया वह अपने आप में अभूतपूर्व है। लाहौर में हुई जनसभा में दस लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया, ऐसी रिपोर्ट है। इस परिस्थिति में कुमारी भुट्टो दमनकारी सैनिक तानाशाही के विरुद्ध लोगों के न्यायसंगत व व्यापक संघर्षों का केन्द्र बिन्दु बनी हुई हैं। साथ ही साथ कुमारी भुट्टो को व्यापक वर्ग और यहां तक कि सेना के एक तबके का समर्थन भी मिल रहा है। राष्ट्रीय असेंबली में निर्वाचित स्पीकर को हटाए जाने व अन्य घटनाएं इस बात की पुष्टि करती हैं।

जनतन्त्र की बहाली के लिए आन्दोलन

अन्य विपक्षी पार्टियों सहित बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पी.पी.पी.) के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप ही कई वर्ष पहले जनरल जिया के दमनकारी शासन के विरोध में लोगों के प्रतिरोध को संगठित करके संघर्ष की शुरूआत की गई थी। उस समय नागरिक स्वतंत्रता के पूर्ण निरोध के विरुद्ध, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिये, सामाजिक, राजनीतिक जीवन के जनवादी मान्यताओं और मूल्यों के पूर्ण निरादर के विरुद्ध तथा सर्वव्यापक आर्थिक शोषण के विरुद्ध लोगों में जो रोष पनप रहा था, उस रोष को जनतन्त्र की बहाली के इस आंदोलन में संचालित करने का प्रयास किया गया था। एक समय ऐसा भी आया जब इस दमघोंटू स्थिति और असीम कष्टों से बाहर आने के लिये छटपटाती जनता ने ताजा चुनाव कराने का नारा लगाया। इस नारे के दबाव में सैनिक शासकों की सीधी देखरेख में निर्दलीय चुनाव कराए गए। इस प्रकार बनी 'नागरिक' सरकार पूरी तरह सेना के नियंत्रण में थी। यह कोई अचम्भे की बात नहीं थी। इसी समय बेनजीर भुट्टो का आविर्भाव हुआ। उन्होंने जनतन्त्र की बहाली और विस्तार के लिए आन्दोलन का आह्वान किया, तथा पूर्णतया स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की। उनके इस आह्वान को तब से अभूतपूर्व जन-समर्थन मिल रहा है।

जिया की मुश्किल

जनरल जिया ने सोचा था कि राष्ट्रीय व प्रांतीय असेंबली के निर्दलीय चुनावों के द्वारा सर्वोच्च सेनानायक की वर्दी में तथाकथित नागरिक सरकार का स्व-नियुक्त राष्ट्रपति बनने पर पाकिस्तान की जनता का विरोध समाप्त हो जाएगा। लेकिन वे पाकिस्तान की जनता की जनतांत्रिक चाह व आकांक्षा को समझने में चूक कर गए। हर तानाशाह से यही चूक होती आई है। जनतांत्रिक शासन की बहाली के लिए बेनजीर के आह्वान को जनता का जो समर्थन मिल रहा है, उससे यह जाहिर हो जाता है कि जनरल जिया द्वारा किए गए धोखे के प्रति लोगों का असन्तोष कितना गहरा और व्यापक है।

जनता के उबलते आक्रोश ने जनरल जिया के प्रशासन के कमजोर हाथ को हिला कर रख दिया है। प्रेस रिपोर्ट से पता चलता है कि सही निर्वाचन द्वारा नागरिक शासन स्थापित करने की मांग का राष्ट्रीय असेंबली के 160 सदस्यों ने समर्थन किया है। राष्ट्रीय असेंबली के स्पीकर फखर इमाम, जो एकमात्र निर्वाचित स्पीकर हैं, ने राष्ट्रीय असेंबली के एक सदस्य द्वारा उठाए गए इस मुद्दे से सहमति जताई है कि जनरली मुस्लिम लीग के संगठीकरण के पहले ही प्रधान मंत्री श्री जुनेजो और अन्य प्रांतीय मुख्यमंत्रियों को इसमें शामिल होने की अनुमति देकर कानून संशोधन से एक असंवैधानिक निर्णय लिया है। इसका अर्थ है कि इन लोगों का चुनाव असंवैधानिक है। श्री इमाम ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है कि अपने आपको 'नागरिक' शासन का राष्ट्रपति घोषित करने के बाद भी जिया सर्वोच्च सेनानायक के पद पर बने रह सकते हैं, अथवा नहीं। जिया और उनके लोगों ने इस गंभीर खतरे को भांप कर श्री इमाम को स्पीकर पद से हटा दिया है। इससे मामला ठंडा पड़ने वाला नहीं बल्कि जिया द्वारा संसदीय सत्ता में लाए गए लोगों का एक प्रभावशाली तबका इस मामले को उठाएगा।

पाकिस्तान की राजनीति में अमरीका की भूमिका

एक बात और ध्यान देने की है। यह है सैन्य व अन्य प्रकार की सहायता देने के कारण पाकिस्तान में अमरीकी हितों का मामला। वास्तव में अमरीका द्वारा दी गई सहायता अथवा पाकिस्तान को दिया गया ऋण इतना बड़ा है कि वस्तुतः पाकिस्तान अमरीका के कर्जे के जाल में फंसा हुआ है। यह भी सभी जानते हैं कि अमरीका, पाकिस्तान को सैनिक अड्डे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है।

अपने स्व-निर्वासन से पहले बेनजीर भुट्टो अमरीका गई थीं। वहां उन्होंने उच्च स्तर के अधिकारियों और नेताओं से बातचीत की थी। संतुलन बनाए रखने के लिये उन्होंने बाद में रूस की यात्रा भी की थी। आज अमरीका के नीति निर्धारक ईरान, वियतनाम व निकारागुआ के अपने अनुभवों से सीख ले चुके हैं। अतएव वे पूरी तरह निरंकुशता को चुके शासन के साथ चिपके रहकर वे अपना अड्डा नहीं खोना चाहते, न ही अपने शिकंजे में ढील आने देना चाहते हैं। वे एक सक्षम विकल्प की आवश्यकता अनुभव कर रहे हैं, इसी उद्देश्य से वे अपनी संभाव्य योजना बना रहे हैं। बेनजीर भुट्टो उनकी योजना का एक अंग हो सकती हैं। वर्तमान परिस्थितियों में आज पाकिस्तान में घट रहे घटनाक्रम से संबंधित ये कुछ तथ्य हैं।

बेनजीर का खेल

'नागरिक शासन' के दिखावे में चल रहे जिया के सैनिक शासन से तंग हुए पाकिस्तानियों के प्रयास से बेनजीर भुट्टो अल्पसंख्यक राष्ट्रीयता के लोगों के बीच गंभीर असंतोष के सभी कारणों को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रही हैं। पाकिस्तान की सत्ता पर औद्योगिक-सैनिक गुट का कब्जा है। इस गुट पर पंजाब के उच्च सैनिक अधिकारियों और उद्योगपतियों का आधिपत्य है। यह सत्ताधारी वर्ग पंजाबी जनता व छोटे सैनिक अधिकारियों सहित आम लोगों पर तीव्र सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक दमन चला रहा है। अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं को बहुसंख्यक राष्ट्रीयताएं दबा रही हैं। इस आधिपत्य और अनेक प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध सिंधी, बलूच व पख्तून लंबे वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं।

राष्ट्रीय उत्पीड़न की शिकार बलूचिस्तान, सिंध तथा उत्तर-पश्चिमी सीमान्त प्रदेश की अल्पसंख्यक 'राष्ट्रीयताएं' जिया के सैनिक शासन के विरुद्ध हो गई हैं उनका रोष भड़क उठा है। जिसकी वजह से राष्ट्र के विखण्डन के खतरे की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस समस्या ने शासक वर्ग को चिन्तित कर दिया है। अफगानिस्तान में चल रहे घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में शासक वर्ग राष्ट्र की एकता और अखण्डता को बनाए रखना चाहता है। अब बेनजीर अमरीका के रणनीति निर्धारकों की सही पसन्द बन रही हैं

(शेष पृष्ठ 3 पर)

असम गण परिषद् सरकार द्वारा अनुचित भाषा नीति स्वीकृत

असम गण परिषद सरकार ने प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से एक परिपत्र जारी करके माध्यमिक स्तर में असमिया भाषा के शिक्षण को अनिवार्य बना दिया है। इस स्तर में गैर असमिया भाषा-भाषी छात्रों को भी असमिया अब अनिवार्य रूप से पढ़नी पड़ेगी। भाषाई अल्पसंख्यकों के बीच इस परिपत्र (Circular) की तीखी प्रतिक्रिया हुई है। यह स्वाभाविक भी है। इस परिपत्र को वापस लेने की मांग प्रदेश में एक व्यापक आन्दोलन का रूप लेती जा रही है। अ.ग.प. सरकार विरोध के इस स्वर को कुचल देने के प्रयत्न में जुट गई है। गत 5 जून को सिलचर रेलवे स्टेशन पर शान्तिपूर्ण ढंग से पिकेटिंग करते प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने अंधाधुंध गोली-चालन किया। गंभीर रूप से घायल हुए प्रदर्शनकारियों को भारी संख्या में अस्पताल में भरती कराना पड़ा। पुलिस के इस बर्बर कृत्य के कारण प्रदेश के अनेक भागों में लोग आन्दोलन में कूद पड़े हैं। नागरिक जनता व अन्य वर्गों के भाग लेने से आन्दोलन [illegible] तक बन चुकी है। इस अन्यायपूर्ण भाषा नीति को अपना कर अ.ग.प. सरकार ने अपना संकीर्णतावादी चरित्र उजागर कर दिया है। यह स्पष्ट हो गया है कि जनतंत्र और सांप्रदायिक सद्भाव का नाम लेते हुए यह सरकार भी सत्ता में आकर अपनी पूर्ववर्ती कांग्रेसी सरकारों की भांति ही अल्पसंख्यकों का दमन करने की नीति को ही आगे बढ़ा रही है। यह बात भी प्रमाणित हो चुकी है कि सरकार चाहे कितना भी बर्बर होकर दमनात्मक कार्रवाई क्यों न करे, अन्यायपूर्ण नीतियों के विरोध में उठे जनता के एकजुट स्वर को दबाया नहीं जा सकता। (विस्तृत लेख अगले अंक में)

विचित्र नशा

लगभग दो साल देश की जनता का मन बहलाव करने के लिए तरह-तरह के तमाशों का आयोजन होता रहता है। क्रिकेट की एक स्थाई तमाशा है ही, जिसमें पिछले दिनों मैक्सिको में हुए फुटबाल के तमाशे को भी उपग्रह के जरिए पर करोड़ों रुपया खर्च करके राजीव गांधी की 'जनहितैषी' सरकार ने देश की भूखी-नंगी जनता के मनोरंजनार्थ प्रस्तुत किया। हमारा देश से कोई विरोध नहीं, लेकिन सिर्फ टेलीविजन पर माराडोना के करतब देखकर कोई माराडोना नहीं बन सकता है। हम भी चाहते हैं कि हमारे देश में भी माराडोना, प्लेटिनी और प्लातिनी जैसे खिलाड़ी हों। ऐसे खिलाड़ी उत्पन्न करने के लिए पहली आवश्यक शर्त है देश की जनता को पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य व अन्य सुविधाएं मयस्सर उपलब्ध हों। लेकिन हमारे देश में देखने को मिलता है कि अनेक प्रतिभाएं उभरने से पहले ही अपर्याप्त सुविधाओं और प्रोत्साहन के अभाव में दम तोड़ देती हैं। ऐसी स्थिति में इन तमाशों के आयोजन का क्या तात्पर्य है?

कितना विचित्र लगता है जब परिवार के परिवार रात-रात भर जागकर टी.वी. पर फुटबाल देखते हैं, फिर दिन भर रात के खेल के बारे में चर्चाएं होती हैं। घर बाहर दफ्तर में या बस-स्टैंड पर एक ही चर्चा। घोर आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक संकट की छाया में जी रही जनता सब कुछ भूलकर टी.वी. के चिपकी बैठी है। आसमान छूती मंहगाई, व्यापक बेरोजगारी, प्रशासनिक भ्रष्टाचार सूखा, बाढ़, साम्प्रदायिक दंगे ये सभी समस्याएं एक तरह से गौण हो जाती हैं। दिमाग पर छाए हैं माराडोना और चपिल देव। इसमें सरकार और शासक वर्ग की साजिश समझी जा सकती है। इनका तो उद्देश्य ही है जीवन के असली मसलों से लोगों का ध्यान हटाए रखना। इस मकसद में वह कामयाब भी हो रही है।

सम्पादकीय

लेकिन जब इतनी सहजता से देश की जनता इस साजिश का शिकार बनती है तो आश्चर्य होता है। जीवन के मूलभूत प्रश्नों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए जिस प्रकार देश में रेडियो और टेलीविजन का दुरुपयोग किया जा रहा है, वह गहन चिंता का विषय है। प्रचार माध्यमों द्वारा अनेक प्रकार से लोगों की रुचि को भी विकृत किया जा रहा है। अश्लीलता प्रदर्शन और उद्देश्यहीन कथानकों पर आधारित कार्यक्रम नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों का नौजवानों के अपरिपक्व मस्तिष्क पर विशेष रूप से बहुत गहरा असर पड़ता है। वे वास्तविकता को भूल कर कल्पना की दुनिया में विचरण करने लगते हैं तथा उनमें उद्देश्यपूर्ण जीवन के प्रति कोई लगाव नहीं रह जाता।

देश की वर्तमान संकटग्रस्त पूंजीवादी व्यवस्था ऐसे जोशीली और चौकन्नेहीन नौजवानों से सबसे ज्यादा खौफ खाती है, जो समाज के सत्य को समझकर उसे बदलने के कार्य में अपनी क्रांतिकारी भूमिका निभाने को तत्पर रहते हैं। यही वजह है कि इस प्रचार के माध्यमों द्वारा ऐसे नौजवानों के उत्पन्न होने की प्रक्रिया में ही बाधा पहुंचाई जा रही है। देश की मेहनतकश जनता और युवा वर्ग को शासक वर्ग की इस साजिश के प्रति सचेत होना पड़ेगा।

यदि खेल-प्रेम की भावना का प्रश्न है तो उसके लिए देश के तमाम प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बिना भेद-भाव के अच्छा आहार, स्वास्थ्य सुविधाएं व अन्य साधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार को मजबूर करना होगा। देश की जनता के गाढ़े पसीने की कमाई द्वारा टेलीविजन और रेडियो पर इन तमाशों को प्रायोजित करने से न ही देश में खेल का भला हो सकता है और न ही खिलाड़ियों का। इस प्रकार तो आम जनता की मानसिकता को ही भ्रष्ट बनाया जा सकता है।

महाराष्ट्र

क्लोजर के विरुद्ध संयुक्त आंदोलन

नागपुर एम्प्रैस मिल के क्लोजर के विरुद्ध विरोधी दलों के संयुक्त आंदोलन में एस॰ यू॰ सी॰ आई॰ ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अन्य दलों के नेताओं सहित एस॰ यू॰ सी॰ आई॰ के जिलिस्ट संगठक कामरेड पी॰ आर॰ दुबे एवं माधव घोंडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

एम्प्रैस मिल महाराष्ट्र के सबसे पुराने मिलों में से एक है। एक समय था जब इस मिल में बाईस हजार श्रमिक काम करते थे। टाटा समूह द्वारा परिचालित इस मिल में युक्तिकरण ढंग से श्रमिकों की संख्या घटाई जाती रही और आज मात्र सात हजार श्रमिक इस मिल में कार्य कर रहे हैं। इससे भी मालिकों को सन्तोष नहीं हुआ और उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की बिना अनुमति मिल की एकमात्र ट्रेड यूनियन, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ से साठ-गांठ करके गत 6 मई से मिल में क्लोजर लागू कर दिया।

इस संकटपूर्ण स्थिति में वामपंथी व विरोधी दल आगे आए। एस॰ यू॰ सी॰ आई॰, सी॰ पी॰ आई॰, सी॰ पी॰ एम॰, जे॰ पी॰ व आर॰ पी॰ आई॰ के सम्मिलित प्रयास से "आल आर्गेनाइजेशन ज्वाइंट सेव एम्प्रैस मिल कुनाईटेड एक्शन कमेटी" का जन्म हुआ। कमेटी के प्रयास से गत 26 मई को नागपुर में एक विशाल विरोध सभा का आयोजन हुआ। उस दिन इस क्षेत्र का दौरा कर रहे उपराष्ट्रपति वेंकटरमन के पास एक प्रतिनिधि-मंडल भी भेजा गया।

इस विरोध प्रदर्शन को छिन्न भिन्न करते हुए पुलिस ने कामरेड दुबे सहित अन्य नेताओं को गिरफ्तार किया। काफी रात को पुलिस ने भारी संख्या में मिल को घेर लिया।

6 मई, क्लोजर के दिन संग्राम कमेटी ने 'जाला तोड़ो' कार्यक्रम के अन्तर्गत मिल के गेट पर विशाल विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर भारी लाठीचार्ज किया और एक बार फिर कामरेड दुबे और कामरेड माधव घोंडे सहित अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया।

टाटा समूह के इस श्रमिक विरोधी रवैये और महाराष्ट्र सरकार की टाटा के हितरक्षाकारी समझौतावादी भूमिका के विरुद्ध 'संयुक्त संग्राम कमेटी' का आन्दोलन जारी है। पता चला है कि क्लोजर समाप्त होने तक आन्दोलन चलता रहेगा।

दिल्ली टैक्सटाइल मजदूरों की हड़ताल का समर्थन

एस॰ यू॰ सी॰ आई॰ (लें॰ मा॰) की दिल्ली राज्य कमेटी ने पांच टैक्सटाइल मिलों में चल रही मजदूरों की एक मास से भी अधिक लंबी हड़ताल के प्रति अपना समर्थन जताया है। राज्य कमेटी ने मजदूरों की मांगों के प्रति मालिक वर्ग के उपेक्षापूर्ण रवैये की कड़े शब्दों में निंदा की है।

यू॰ टी॰ यू॰ सी॰ (लें॰ मा॰) का

चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल रूस में

नई दिल्ली। रूस की आल यूनियन सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन्स (ए.यू.सी.सी.टी.यू.) के निमंत्रण पर यू.टी.यू.सी. (लें॰मा॰) का चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल रूस में शिक्षण यात्रा (study tour) में भाग लेने गया है। इस यात्रा में भाग लेने के लिए यू.टी.यू.सी.(लें.मा.) की अखिल भारतीय कमेटी ने बेलिहुर मजदूर यूनियन हिरयाणा के सचिव का॰ सत्यवान, बिहार कोल मजदूर यूनियन के सचिव का॰ अविन सरकार, दुर्गापुर स्टील वर्कर्स एसोसिएशन कमेटी के उपाध्यक्ष का॰ एस.सी. राय तथा प॰ बंगाल जूट मिल वर्कर्स यूनियन के सचिव का॰ दलीप महाचार्य को शिक्षण यात्रा में भाग लेने के लिए नामजद किया है। प्रतिनिधिमंडल 30 मई 1986 को मास्को के लिए रवाना हो गया। रूस में यह प्रतिनिधिमंडल ए.यू.सी.सी.टी.यू. द्वारा आयोजित ट्रेड यूनियन कोर्स व उच्चतर ट्रेड यूनियन शिविर में भाग लेगा। यह प्रतिनिधिमंडल 35 दिन तक रूस में रहेगा तथा अपने प्रवास के दौरान ताशिकिस्तान व अन्य स्थानों के सामूहिक व को-आपरेटिव कृषि फार्मों सहित अन्य उद्योगों का भी दौरा करेगा। मास्को से प्राप्त होने वाली डाक के अनुसार प्रतिनिधिमंडल आगामी 6 जुलाई को भारत लौट आएगा।

प॰ बंगाल

बस-भाड़ा वृद्धि के विरोध में व्यापक जनान्दोलन का उभार

जनमत की अवहेलना करते हुए प॰ बंगाल की वाम मोर्चा सरकार ने एक बार फिर बस-भाड़े में वृद्धि कर दी है। बढ़ा हुआ बस भाड़ा 21 जून से लागू होना तय था। प्रदेश की जनता में इस नवीन भाड़ा-वृद्धि के खिलाफ व्यापक आक्रोश व्याप्त है। श्री ज्योति बसु की सरकार का कहना है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा डीजल पेट्रोल व अन्य वस्तुओं के दाम बढ़ाने के कारण मजबूर होकर उसे यह कदम उठाना पड़ा है। यह धोखा तर्क देकर जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। इस भाड़ा-वृद्धि द्वारा बस मालिकों की जेबें पहले से भी भारी हो जाएंगी तथा पहले से ही असहनीय करों के बोझ तले पिसती जनता का जीवन और भी दूभर हो जाएगा।

(शेष पृष्ठ 3 पर)

पाकिस्तान......

(पृष्ठ 1 का शेष)

है कि वे जनरल जिया से स्पष्ट व पूरी तरह विश्वसनीयता खो चुके शासन को अपना समर्थन देना बंद कर दें, क्योंकि जनरल जिया पाकिस्तान को कमजोर बना रहे हैं। अपने देश की जनता की राष्ट्रीय भावनाओं का भी वे यह कह कर लाभ उठा रही हैं कि सैनिक शासन द्वारा अराजक बना दी गई स्थिति को और अराजक न होने दिया जाए। उनका कहना है कि इस सरकार को सत्ता में रखकर देश के दुश्मनों को ही फायदा मिलेगा। जनरल जिया और उनके गुट पर हमला करते समय कुमारी भुट्टो तथाकथित नागरिक सरकार के प्रधानमंत्री श्री जुनेजो को साफ बचा जाती हैं। इस प्रकार जनरल जिया और उनके कट्टर समर्थकों पर अपना हमला केंद्रित करते हुए बेनजीर, नौकरशाह सैनिक अधिकारियों सहित अन्य लोगों को अपने पक्ष में करने की महत्वाकांक्षी कोशिश कर रही हैं। लाहौर में जिस प्रकार उनका स्वागत हुआ, उससे उनके प्रति बढ़ते जनसमर्थन का संकेत मिलता है।

चेतावनी

ध्यान देने की बात यह है कि बेनजीर ने अब तक एक भी अमरीका विरोधी बात नहीं कही है। अतः प्रश्न उठता है कि उनका दूरगामी राजनीतिक स्टैंड और दृष्टिकोण क्या होगा? स्वतन्त्र व निष्पक्ष ताजा चुनावों की उनकी मांग को सरकार के एक तबके का भी ठोस समर्थन मिला है। यहां तक की श्री जुनेजो भी इस मांग से दूर दिखाई नहीं देते। जनरल जिया अपना समर्थन लगातार कम होते देखकर बिल्कुल कोने में आ गए हैं। इस स्थिति में फंसकर वे चिल्ला रहे हैं कि पाकिस्तान को अस्थिर बनाने के लिए रूस और भारत उनके विरोधियों का साथ दे रहे हैं। इस स्थिति से लाभ उठाने के लिए भारतीय शासक पूंजीपति वर्ग के पास कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन जनरल जिया लोगों का ध्यान बंटाने के लिये ही यह शोर मचा रहे हैं। ऐसा करके वे इस्लामिक देशों से सहायता पाने के लिये मुस्लिम कठमुल्लाओं को भी गोहार के रूप में इस्तेमाल करेंगे।

हम गहरी सहानुभूति के साथ सैनिक तानाशाही के विरुद्ध, जनवादी अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं की बहाली के लिये पाकिस्तान की जनता के इस न्यायोचित संघर्ष का अभिनन्दन व भरपूर समर्थन करते हैं। हम उनकी ताजा, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव की मांग का भी समर्थन करते हैं। ये चुनाव पूरी तरह स्वतंत्र और जनवादी वातावरण में होने चाहिएं, सैनिक शासन की निगरानी में नहीं।

इस आंदोलन को और भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस दमनात्मक भ्रष्ट शासन को अलग-थलग करने के लिए और भी व्यापक जनसमर्थन जुटाना होगा। जुल्फकार अली भुट्टो की पुत्री होने के नाते बेनजीर के प्रति पाकिस्तान की जनता में व्यापक सहानुभूति है। जिस घृणित तरीके से श्री भुट्टो की न्यायिक हत्या की गई थी इस सहानुभूति का यह एक मुख्य कारण बना है। इसी सहानुभूति के कारण जनवाद की बहाली के देशव्यापित पूर्ण संघर्ष में सभी पाकिस्तान की जनता बेनजीर की राष्ट्रीय बुर्जुआ पार्टी—पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की ओर नेतृत्व के लिये आशा की नजरों से देख रही है।

जिस प्रकार दुनिया की दो महाशक्तियां पाकिस्तान की इन घटनाओं में रुचि ले रही हैं, उसे देखकर प्रश्न उठता है कि पाकिस्तान के भाग्य का निर्णय कौन करेगा? पाकिस्तान की जनता को स्वयं ही अपने भाग्य का फैसला करना चाहिए, आगे के लिये अपनी प्रगति का रास्ता तय करने का अधिकार उन्हीं का है। हमारा अनुभव बताता है कि जब चुनाव के माध्यम से अथवा लोगों की कुर्बानी और संघर्ष का फायदा उठाकर राष्ट्रीय बुर्जुआ पार्टियां सत्तासीन होती हैं, तब थोड़े ही समय में वे जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भुलाकर यह सिद्ध करने लग जाती हैं कि निरंकुशता के मामले में वे उन ताकतों से कम नहीं हैं, जिन्हें उखाड़ फेंककर वे सत्ता में आई थीं। बंगलादेश इस बात का नवीनतम प्रमाण है। ये पार्टियां पूंजीपति के हितों की रक्षा करते हुए शासक वर्ग की विश्वासपात्र एजेंट की भूमिका अदा करती हैं तथा स्वयं तरह-तरह से लोगों के जनवादी अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं पर रोक लगाती हैं। अतः पाकिस्तान में घृणित सैनिक तानाशाही का खात्मा हो जाने के बाद भी जनता को स्वतंत्रता व जनवाद की बहाली व विस्तार के लिए संघर्ष करने को तैयार रहना होगा। वास्तविक मुक्ति प्राप्त करने की राह में संग्राम का मौजूदा दौर एक शुरुआत है, अन्त नहीं।

बस भाड़ा वृद्धि......

(पृष्ठ 2 का शेष)

भारत की मेहनतकश जनता की सच्ची हिमायती पार्टी एस. यू. सी. आई. और क्रांतिकारी छात्र संगठन ए. आई. डी. एस. ओ. ने तुरंत प० बंगाल सरकार के इस जनविरोधी रवैये के विरुद्ध प्रदेश के हर जिले में प्रबल आंदोलन खड़ा कर दिया है। अनेक स्थानों पर यात्रियों ने बढ़े हुए बस भाड़े देने से इंकार कर दिया। जगह-जगह पर आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ, व्यापक पैमाने पर गिरफ्तारियां की गईं, लेकिन आन्दोलन पार्टी के सुयोग्य नेतृत्व में पूरे प्रदेश में व्यापक जनसमर्थन के बल पर और पकड़ता जा रहा है। प० बंगाल की वाम मोर्चा सरकार जिस प्रकार बार-बार बस भाड़े में वृद्धि कर रही है, उससे इस सरकार के 'जनप्रेम' की पोल लगातार खुलती जा रही है। इस सरकार को समझ लेना होगा कि जनता सरकार के इस अत्याचार को मौन रह कर स्वीकार नहीं कर सकती।

प० बंगाल

पौर निर्वाचन

प० बंगाल में गत जून में हुए पौर निर्वाचन में एस.यू.सी.आई. ने अकेले अपने बूते पर वाम मोर्चे और कांग्रेस (इ) का एक साथ मुकाबला करते हुए अनेक पौर परिषदों में उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है। हमेशा की तरह बुर्जुआ समाचार पत्र इस बार भी एस.यू.सी.आई. की इस सफलता का उल्लेख करना भूल गए। हां, जिन-जिन स्थानों पर एस.यू.सी.आई. का प्रबल संगठन है, उन स्थानों पर ये समाचार पत्र पार्टी विरोधी अभियान चलाना और निराधार आरोप लगाना नहीं भूले।

पुरुलिया जिला की रघुनाथपुर पौर-परिषद में 11 में से 5 स्थानों पर, मुर्शिदाबाद में 2 स्थानों पर, [illegible] जिला की [illegible] में दो स्थानों पर, उत्तरी बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक स्थान पर तथा दक्षिण चौबीस परगना में जयनगर में 4 स्थानों पर एस.यू.सी.आई. के उम्मीदवारों ने विजयश्री अर्जित की। उल्लेखनीय है कि जयनगर में इस बार सी.पी.आई.(एम.) ने एस.यू.सी.आई. के साथ चुनाव में गठबंधन किया था, फलस्वरूप वहां आज तक पहले कभी सी.पी.आई.(एम.) का उम्मीदवार विजयी नहीं हुआ था वहां उसे भी एक स्थान पर विजय मिली।

अन्य स्थानों के चुनाव परिणाम अभी नहीं मिले हैं।

ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधिमंडल का पंजाब दौरा

नई दिल्ली में 11 मई को साम्प्रदायिक व पृथकतावादी शक्तियों के विरोध में हुए केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रीय सम्मेलन के एक निर्णय के अनुसार केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के छः सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने 11 से 13 जून तक पंजाब का दौरा किया। यू.टी.यू.सी. (ले० स०) के उपाध्यक्ष का० करम सिंह, एटक के अध्यक्ष चतुरानन मिश्र, सीटू के महासचिव समर मुखर्जी, इंटक के एम.एम. शर्मा, भारतीय मजदूर संघ के सचिव आर० के० भक्त तथा हिन्द मजदूर सभा के उपाध्यक्ष कमला सिन्हा प्रतिनिधि मंडल के सदस्य थे। प्रतिनिधि मंडल का उद्देश्य प्रांत के लोगों के बीच साम्प्रदायिक सद्भाव और आपसी भाईचारे को मजबूत करना था।

प्रतिनिधिमंडल ने अमृतसर में तरन-तारन, जंडियालागुरु व [illegible] नगर का दौरा किया। उन्होंने सभी तबके के लोगों से मुलाकात की। हर स्थान पर प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। लोगों ने दिल खोल कर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से बातचीत की। एक बात उभर कर जो सामने आई वह यह थी कि हर तबके और समुदाय के लोग पंजाब में चल रही अस्थिरता व असुरक्षा की स्थिति के अन्त से ... वे जल्द से जल्द इस समस्या का स्थाई समाधान चाहते हैं। उनकी आकांक्षा है कि पंजाब में पहले की तरह शांति स्थापित हो, जनजीवन सामान्य हो और कारोबार पहले के समान चल निकले।

12 जून को अमृतसर में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस सभा में प्रांतीय ट्रेड यूनियन नेताओं ने भी भाग लिया। हजारों-हजार की संख्या में लोगों ने ट्रेड यूनियन नेताओं के भाषणों को ध्यानपूर्वक सुना। सभा के बाद एक विशाल शांति यात्रा निकाली गई। चिलचिलाती धूप के बावजूद हजारों स्त्री, पुरुष और बच्चों ने इस यात्रा में भाग लिया। जुलूस में सभी सम्प्रदायों के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

13 जून को प्रतिनिधिमंडल ने जालंधर की यात्रा की। यहां भी एक विशाल जन सभा हुई और बाद में एक लम्बा जुलूस निकाला गया। इन सभाओं में सभी ट्रेड यूनियन नेताओं ने इस बात पर बल दिया कि साम्प्रदायिक सद्भाव कायम करने के लिए आवश्यक है कि धर्म को राजनीति से अलग किया जाए। जो सामाजिक शक्तियां आज लोगों को धर्म के आधार पर बांट कर लोगों की साम्प्रदायिक भावनाओं से खेल रही हैं, वे जाने अनजाने में शासक पूंजीपति वर्ग के ही हाथ मजबूत कर रही हैं। लोगों के बीच फूट डालने वाली ऐसी शक्तियों को पहचान कर अलग थलग किया जाना चाहिये।

हड़ताल के प्रसंग में

—लेनिन

ज्यों-ज्यों फैक्ट्री उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगता है वैसे ही हड़ताल भी होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? इस का कारण है - पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था में मालिक के विरुद्ध मजदूर की लड़ाई अनिवार्य है। जब उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगता है तो मालिक के विरुद्ध मजदूर की लड़ाई की यह अनिवार्यता हड़ताल का रूप धारण कर लेती है।

पूंजीवाद एक ऐसी समाज-व्यवस्था है जिसमें एक ओर तो जमीन, कल-कारखानों और मशीन इत्यादि पर मुट्ठी भर पूंजीपति और धनी किसानों का मालिकाना होता है तथा दूसरी ओर अधिसंख्य लोगों के पास नाममात्र की थोड़ी-बहुत जमीन रहती है, अथवा वह भी नहीं। ये लोग अपना सब कुछ गवां कर जीवित रहने के लिए अपना श्रम बेचने को बाध्य होते हैं। कारखानों के मालिक और पूंजीपति उनकी श्रम शक्ति को खरीद कर, उसका उपयोग करते हैं। इस श्रम शक्ति से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करके बाजार में बेचा जाता है। कारखानों के मालिक श्रमिकों को उनके श्रम के बदले उतनी ही मजदूरी देते हैं, जितने से श्रमिक और उनके परिवार के लोग किसी प्रकार जीवित रह सकें। श्रमिक जो उत्पादन करते हैं, उसके बाकी सारे मूल्य को पूंजीपति, मुनाफे के रूप में अपनी जेब में रख लेते हैं। इसीलिए पूंजीवादी व्यवस्था में अधिसंख्य लोग पूंजीपतियों के भाड़े के गुलाम होते हैं। वे अपने लिए नहीं बल्कि मजदूरी के बदले मालिक के लिए काम करते हैं। स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में मालिक मजदूरों की मजदूरी घटाने की कोशिश करते हैं। मजदूरी जितनी कम होगी मालिकों का मुनाफा भी उतना ही अधिक होगा। दूसरी ओर अपने व अपने परिवार के लिये भरपेट पौष्टिक भोजन की, अच्छे निवासस्थान की व अच्छे वस्त्रों की व्यवस्था करने के लिये मजदूर हमेशा चेष्टा करता रहता है ताकि वह भी भिखारियों के समान न रह कर अन्य लोगों की भांति रह सके। इसीलिये मजदूरी (Wages) को लेकर मालिक और श्रमिकों के बीच निरन्तर संघर्ष चलता रहता है। मालिक किसी भी मजदूर को काम पर रखने को स्वतंत्र है। वह सबसे सस्ते मजदूर को ही काम पर लगाता है। मजदूर भी अपना मालिक चुनने को स्वतंत्र है। अतः वह ऐसा मालिक चुनने की कोशिश करता है जो उसे अधिक से अधिक मजदूरी दे। मजदूर चाहे शहर में काम करता हो या गांव में, चाहे वह किसी भू-स्वामी के यहां अपना श्रम बेचता हो चाहे किसी धनी किसान, ठेकेदार अथवा फैक्ट्री-मालिक के पास वह हमेशा मालिक के साथ मोल-भाव करता है तथा मजदूरी को लेकर उसके साथ संघर्ष करता है।

सवाल यह उठता है कि अकेला रह कर क्या कोई मजदूर इस लड़ाई को चला सकता है। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिये हमें वर्तमान परिस्थिति पर नजर डालनी होगी। हम देखते हैं कि आज अनगिनत लोग बेकार हैं, उन्हें काम मिलने की कोई आशा भी नहीं है; तथा बेकारी की यह संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस पर गांव के गरीब किसान अथवा खेतिहर मजदूर; अपनी जमीन से हाथ धोकर काम की तलाश में शहरों और औद्योगिक नगरों व केन्द्रों की ओर विशाल संख्या में आते जा रहे हैं। दूसरी ओर धनी किसान और पूंजीपति नित्य नई-नई मशीनें लगाकर काम के अवसरों को और भी कम करते जा रहे हैं। शहरों की तरफ देखने से पता चलता है कि बेकारों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, उधर गांवों के लोग तेजी से कंगाल होते जा रहे हैं। पूंजीपति आजकल जो भी मजदूरी देना चाहते हैं; भूखमरता लोग उसी को स्वीकार करने को मजबूर हैं। इसी प्रकार प्रतिदिन मजदूरी घटती जा रही है। इस स्थिति में कोई भी मजदूर अकेला मालिक के विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता। यदि कोई मजदूर अकेला उचित मजदूरी की मांग करता है तो फौरन मालिक उससे कहता है, "जाओ! हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। कारखाने के दरवाजे पर ऐसे अनेकों भूखे मजदूर लाईन लगाए खड़े हैं, जो कम मजदूरी पर ही स्वेच्छा से काम करने को तैयार हैं।"

इस निर्मम शोषण से बचने के लिये श्रमिक संगठित होकर लड़ाई करते हैं। पूंजीवादी शोषण उन्हें निश्चित रूप से मृत्यु के मुंह में धकेल रहा है। अतः अकेला रह कर वह पूरी तरह असहाय है। जब श्रमिक जनता इस सच्चाई को समझ जाती है तो वह एकजुट होकर मालिक के विरुद्ध खड़ी हो जाती है। श्रमिकों की हड़ताल का इतिहास इसी प्रकार आरम्भ होता है।

श्रमिक वर्ग की लड़ाई में हड़ताल का तात्पर्य क्या है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हड़ताल के संबंध में एक सर्वांगीण धारणा बनाना आवश्यक है। पहले ही कहा जा चुका है कि पूंजीवादी व्यवस्था में मालिक और मजदूर के समझौते के द्वारा ही मजदूरी का निर्धारण होता है। एक मजदूर अकेला इस संघर्ष को नहीं चला सकता। इसी से अपनी मांग मनवाने के लिये यह आवश्यक है कि मजदूर एकजुट होकर संघर्ष करें। मजदूरी में वृद्धि करने के लिये अथवा मजदूरी के ह्रास को रोकने के लिये बाध्य होकर उन्हें हड़ताल का रास्ता अपनाना ही पड़ता है। इसीलिये जहां-जहां पूंजीवाद है, वहां-वहां हड़ताल भी अनिवार्य है। यूरोप के देश हों अथवा अमरीका; सभी देशों के मजदूर इस सत्य को समझ चुके हैं कि एकता के बिना वे शक्तिहीन हैं। एकताबद्ध होकर हड़ताल कर के अथवा हड़ताल की धमकी द्वारा दबाव डाल कर ही वे मालिक का मुकाबला कर सकते हैं। उनके पास यही एकमात्र चारा है। पूंजीवाद जितना ही अधिक विकसित होता है, बड़े-बड़े कारखाने अस्तित्व में आते चले जाते हैं। बड़े पूंजीपतियों के साथ प्रतियोगिता न कर पाने के कारण छोटे-छोटे पूंजीपति विलुप्त होते चले जाते हैं। बेकारों की संख्या तेजी से बढ़ती चली जाती है। बाजार हथियाने के लिये पूंजीपतियों के बीच संघर्ष तेज होता चला जाता है। पूंजीवादी बाजार की अस्थिरता बढ़ती चली जाती है। संकट तीव्र से तीव्रतर होता चला जाता है। इसी से मालिक पूंजीपति कम से कम खर्च में उत्पादन करना चाहते हैं। वे [illegible] कम मजदूरी देना चाहते हैं। इस परिस्थिति में श्रमिक वर्ग के एकताबद्ध प्रतिरोध को निर्मित करने का महत्व और भी बढ़ जाता है। जब उद्योग धन्धों में तेजी आती है, मालिक विपुल मात्रा में मुनाफा लूटते हैं। किन्तु इस लाभ का थोड़ा बहुत अंश भी मजदूरों को देने की बात उन्हें ख्याल में भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब संकट दिखाई देता है, तब समस्त इस संकट की सारी जिम्मेदारी मजदूरों के कन्धों पर डालने की कोशिश की जाती है। पूंजीवादी व्यवस्था में हड़ताल की अनिवार्यता को भी यूरोपीय देशों ने स्वीकार कर लिया है। कानून के हिसाब से इन देशों में हड़ताल निषिद्ध नहीं है। (भारत में भी हड़ताल को कानूनी मान्यता प्राप्त है)

पूंजीवादी समाज की अन्तर्निहित विशिष्टता के लिए हड़ताल का जन्म होता है, वही हड़ताल पूंजीवादी समाज व्यवस्था के विरुद्ध मजदूर वर्ग के संघर्ष की शुरुआत भी है। जब कोई सम्पत्तिहीन मजदूर अकेला ही धनी पूंजीपति वर्ग के सामने खड़ा हो जाता है। तब मानना होगा कि उसका निरुपाय दासत्व ही एकमात्र सत्य है। लेकिन जिनके पास अपना कहने को कुछ नहीं है, वही श्रमिक-दल जब एकता बद्ध हो जाते हैं, तो परिस्थिति ही बदल जाती है। यदि मालिक अपने कारखानों और मशीनों में मजदूरों की श्रम शक्ति को काम में नहीं लगा पाते हैं; नई सम्पदा तैयार नहीं कर पाते हैं तो कारखानों, मशीनों और कच्चे माल के मालिक होने पर भी वे मुनाफा नहीं कमा सकते।

जितने दिन मजदूर, पूंजीपतियों के व्यक्तिगत और पर संबंध नहीं रखते हैं, उतने ही दिन वे उनके गुलाम बने रहते हैं। रोटी के एक टुकड़े के लिए उन्हें लगातार क्रीतदास के समान, सर झुकाकर दूसरे के लाभ के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन जब श्रमिक एकजुट होकर अपनी मांग उठाते हैं तथा धनवान सेठों के आगे समर्पण नहीं करते, उसी समय उनकी गुलामी समाप्त हो जाती है, वे इन्सान बन जाते हैं। वे मांग करना शुरु करते हैं कि उनके श्रम से मुट्ठी भर निकम्मे लोगों को ही धनी नहीं बनाते रहा जा सकता, बल्कि श्रम करने वालों को भी इन्सान की तरह जीने का अवसर देना होगा।

कांग्रेस (इ०) के गुण्डों द्वारा SUCI संगठक की निर्मम हत्या

जयनगर, प० बंगाल : 6 जून 1986 को दक्षिण चौबीस परगना जिला में जयनगर [illegible] तथा गांव में कांग्रेस (इ) के गुण्डों ने एस.यू.सी.आई. की ग्राम कमेटी के सदस्य का० गोपाल नस्कर पर खतरनाक हमला किया। उन्हें नाजुक अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने पहुंचते ही प्राण त्याग दिये। उनकी माता रोहिणी नस्कर और भाई गंगा नस्कर को भी गंभीर घायलावस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

एस.यू.सी.आई. की प० बंगाल राज्य कमेटी के सचिव का० सुकोमल दासगुप्त ने इस घटना की तीव्र निंदा करते हुए सरकार से मांग की है कि हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, मृतक के परिवार को समुचित मुआवजा दिया जाए तथा घायलों की ठीक से चिकित्सा की जाए।

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इंडिया (एस. यू. सी. आई.) की ओर से ज्ञानसिंह द्वारा 4/11772 करोल बाग, दिल्ली - 5 से सम्पादित व प्रकाशित तथा [illegible] प्रिंटर्स', बी-2633, मेन बस स्टेंड, शिवपुर, दिल्ली - 35 से मुद्रित